उत्तर प्रदेश में आलू नीति बनायी जाएगी: अमर सिंह

लखनऊ, वार्ता।

उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बहुप्रचारित चीनी नीति की तर्ज पर अब आलू नीति तैयार करेगी।

राज्य में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) के महासचिव तथा उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अध्यक्ष अमर सिंह ने यहां उत्तर प्रदेश में 'आलू विकास का परिदृश्य एवं संभावनाएं' विषय पर गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें राज्य की चीनी नीति तैयार करने में एक वर्ष का समय लगा।

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश विधानसभा के चुनाव नजदीक होने के बावजूद वह राज्य में आलू नीति जल्द लागू कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा आलू अनेक व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली चीज है। हमें इसके महत्व को समझना चाहिये।

इस अवसर पर राज्य के कृषि उत्पादन आयुक्त अनीस अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, लेकिन यहां इसके समुचित प्रसंस्करण की नीति को विकसित किया जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा आलू को सुरिक्षत रखने के लिए इस समय राज्य में 1350 अवशीतन गृह हैं लेकिन इनमें विद्युत की खपत ज्यादा होती है। ऐसे अवशीतन गृह विकसित करने की जरूरत है जिनसे कम बिजली खर्च में मनचाहे नतीजे हासिल किये जा सकें।

उन्होंने किसानों के मुनाफे में बढ़ोत्तरी के लिये दुग्ध नीति बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा

भोपाल। ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव एस.एल. भट्ट ने पिछले दिनों आईटीसी के सीहोर चौपाल सागर का दौरा किया। उनके साथ शामिल अन्य लोगों में भारत सरकार के दलहन निदेशक श्री तिवारी, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि महानिदेशालय में उपनिदेशक श्री परमार और श्री वर्मा तथा भोपाल संभाग के कृषि महानिदेशालय के संयुक्त निदेशक श्री राजपूत शामिल थे। इसके अलावा सीहोर जिला के कृषि उपनिदेशक श्री रघु ने भी इस भ्रमण के दौरान अतिथियों का साथ दिया।

चौपाल सागर के प्रबंधक वेंकटराव ने अतिथियों की अगवानी की। उन्होंने अतिथियों को सभी विभागों का भ्रमण कराया तथा लेन-देन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बातचीत के दौरान श्री एस.एल. भट्ट ने बताया कि पिछले साल पाकिस्तान दौरे के दरम्यान उन्होंने आईटीसी के चौपाल सागर के बारे में सुना। इस घटना ने उन्हें चौपाल सागर के भ्रमण के लिए प्रेरित किया। सारी जानकारी लेने और चौपाल सागर के बारे में विस्तार से जानने के बाद सम्मानित अतिथियों ने खरीद स्थल पर किसानों के साथ विचारो का आदान प्रदान किया और सोया की कीमतों तथा चौपाल सागर द्वारा कृषक समुदाय के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर संतुष्टि जाहिर की। चौपाल सागर स्थल के भ्रमण के दौरान सम्मानित अतिथि ने कहा कि मैं यह विश्वास नहीं कर पा रहा कि मैं भारत में इस तरह का निर्माण देख रहा हूं। सम्मानित अतिथियों ने आगन्तुक पंजी में इन शब्दों में अपनी भावना जाहिर की कि ''यह कृषि और प्रबंधन के साथ एकीकृत प्रौद्योगिकी का अनुपम उदाहरण है।''

घरेलू मांग में निखार से गुलाब क्षेत्र का अच्छा भविष्य

मुम्बई, ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

मध्यवर्ग के बीच गुलाब की बढ़ती लोकप्रियता के कारण घरेलू स्तर पर गुलाब की बढ़ती मांग से 800 करोड़ रुपये के गुलाब उद्योग में 25-30 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

पोचीराजू इस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक पी. सुधारकर ने बताया कि पिछले लगभग 5 वर्षों में कट रोज की घरेलू मांग में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है और इस रुख के जारी रहने की उम्मीद है। उन्होंने यह बात कंपनी के पहले पब्लिक इश्यू के अवसर पर यहां कही।

कंपनी कैपिटल मार्केट में 15 जनवरी को पेश करने जा रही है और इसके लिए नये उद्यम हेतु 37.57 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

पोचीराजू ब्रांड के नाम से अपने उत्पादों की बिकवाली करने वाली यह कंपनी मुख्य रूप से उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बाजारों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसका ग्रीन हाउस में गुलाब उत्पादन क्षेत्र लगभग 6 हेक्टेयर है। पश्चिमी भारतीय बाजारों का नियंत्रण पुणे के गुलाब उत्पादकों के हाथों में है।

भारत में चमकीले और रंगीन गुलाबों की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है परन्तु विदेशी बाजारों, खासतौर पर अमरीका और इंग्लैंड के बाजारों में स्वीटहर्ट और इंटरमीटिएट्स किस्मों की सबसे अधिक मांग है।

यद्यपि भारत से प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपये मूल्य के गुलाबों का निर्यात किया जाता है फिर भी विश्व के फूलों के कुल कारोबार में इसकी हिस्सेदारी मात्र 0.5 प्रतिशत है। ऐसे में इस क्षेत्र के विकास की काफी अधिक संभावनाएं हैं। श्री शंकर ने कहा कि विश्व के फूलों के कुल कारोबार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.1 प्रतिशत है। लगभग 64 बिलियन डॉलर के कट रोज के प्रमुख उपभोक्ताओं में अमरीका, कनाडा, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मध्य-पूर्वी देश और न्यूजीलैंड शामिल हैं।

अधिकांश गुलाबों का उत्पादन संरक्षित परिस्थितियों में किया जाता है तथा इन्हें पोली/ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस से ढका जाता है। इसमें तापमान 15-20 डिग्री के बीच बनाकर रखा जाता है। इसके लिए अब प्राकृतिक कुलिंग या हिटिंग पद्धति आर्थिक रूप से सही नहीं है।

दूसरी ओर, नीदरलैंड और अमरीका जैसे देशों में प्राकृतिक रूप से गुलाबों का उत्पादन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कोलंबिया, इस्राइल, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और भारत जैसे विकासशील देश अतिरिक्त उत्पादन केन्द्रों के रूप में उभरे हैं।

मांग में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप भारत और विदेशों में गुलाब के रकबे में स्थिर बढ़वार हो रही है। इस समय विकसित देशों का फूलों के कारोबार में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है जबकि यूरोपीय देश बड़े आयातकों में शामिल हैं।

ऊर्जा पर आने वाले खर्च तथा पर्यावरण स्थितियों के चलते यूरोपीय देश और अमरीका फूलों की अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर ही निर्भर करते हैं।

अरहर में तेजी का रुख, मध्य जनवरी से आवक बढ़ने की संभावना

नई दिल्ली ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

भारत में भोजन के महत्वपूर्ण अंग दाल को हल्के से नहीं लिया जा सकता। अरहर के रूप में मशहूर तूर दाल के भाव बढ़ रहे हैं तथा व्यापारी भी तेजी की धारणा में बैठे दिखाई रहे हैं। एक माह पूर्व ही अरहर दाल में तेजी के संयोग बनने लगे थे। हाजिर व्यापारियों के साथ-साथ स्टॉकिस्टों ने तेजी की संभावना को देखते हुए बिकवाली सीमित कर दी। दूसरी तरफ वायदा में निवेशकों ने 1800 रुपये प्रति क्विंटल पर मार्च डिलीवरी हेतु अच्छी खरीद की। एक माह बाद उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है क्योंकि इसके भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ चुके है।

इस तरह यदि देखा जाये तो जिन निवेशकों ने एक माह पहले अरहर के एक सौदे किये और अगर उन्होंने 9 जनवरी को अपनी पोजीशन खत्म की हो तो उनहें 60,000 रुपये प्रति लॉट का लाभ मिला होगा।

आर्बिट्रेज में भी अवसर दिखाई दिये हैं। एक माह की समयावधि में हाजिर एवं वायदा भाव के बीच अंतर के आधार पर आयातित किस्मों पर निवेश करने पर 5 प्रतिशत एवं घरेलू किस्मों पर 11 प्रतिशत की आय मिली। अगर इसकी गणना वार्षिक आधार पर की जाये तो यह क्रमश: 33 एवं 52 प्रतिशत बैठता है।

गोदाम भाड़ा एवं ब्रोकेज समेत तूर की आयातित किस्मों के हाजिर भाव 2333 रुपये प्रति क्विंटल है। अगर इस भाव पर किसी निवेशक का ओपन पोजीशन अप्रैल अनुबंध बिकवाली के लिए था तथा अगर उसने हाजिर बाजार से 10 टन का एक लॉट खरीदा तथा उसे वायदा बाजार में अपना पोजीशन खत्म करते हुए बेच दिया तो उसे इसमें 132 रुपये का लाभ मिला, अगर हम 2462 रुपये के एनसीडीईएक्स भाव को आधार बनाये। अर्थात एक लाट पर उसे 13200 रुपये का लाभ मिला।

इसी वजह से घरेलू किस्मों के मामले में, जिसका हाजिर बाजार में भाव 2203 रुपये प्रति क्विंटल है एवं वायदा भाव 2465 रुपये हैं, के कारोबार में निवेशकों को 26200 रुपये प्रति लॉट का लाभ मिला होगा। जिंस बाजार से जुड़े व्यापारियों के अनुसार भारत में विश्व का 80 से 85 प्रतिशत तक अरहर का उत्पादन होता है। इस वर्ष देश में मोटे तौर पर 26 लाख टन अरहर उत्पादन होने का अनुमान है। मांग के मुकाबले यह अभी भी 3 से 4 लाख टन कम माना जा रहा है।

भारत में अरहर की कमी की भरपाई म्यांमार एवं तंजानिया से आयात के मार्फत की जाती है। हालांकि, वर्ष 2006 में उड़द की अच्छी मांग के कारण इन देशों ने अपना ध्यान उड़द की तरफ भी केन्द्रित किया। इसलिए इस जिंस में भी सुधार देखने को मिल रहा है। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में फसल को नुकसान तो पहुंचा ही, तेजी की धारणा को देखते हुए आवक भी कमजोर पड़ने लगी जिससे आपूर्ति प्रभावित हो रही है। लेकिन मध्य-जनवरी से आवक में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।

मुम्बई के एक अन्य व्यापारी ने बताया कि गुलबर्गा में अभी 17 से 18 हजार बोरियों की आवक हो रही है। अगले सप्ताह से आवक और बढ़ेगी जिससे यह संकेत मिलेगा कि कमी कितनी गंभीर है इस फसल की बिजाई गर्मी में होती है। जून एवं जुलाई माह के दौरान यह फसल लगाई जाती है। दो सप्ताह में यह अंकुरित होने लगता है। अक्टूबर माह में फसल में फूल लगते हैं। दिसम्बर, जनवरी माह में फसल कटने लगती है।

कृषि हब के बारे में रेलवे की वृहत योजना

नई दिल्ली ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

रेलवे मंत्रालय कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए मूल नीति बनाने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में मंत्रालय आईटीसी जैसे बड़े खुदरा कारोबार से जुड़ी कंपनियों के साथ संपर्क में हैं। इस नई पहल के

तहत रेलवे अपनी भूमि के उपयोग के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले को कृषि खुदरा हब को स्थापित करने की अनुमति देगा। रेलवे को उम्मीद है कि प्रत्येक हब पर लगभग 200 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। कुल मिलाकर ऐसे 16 हब स्थापित किये जायेगे जिनमें से एक-एक चारों मेट्रो शहरों में होंगे।

हब एंड स्पोक पद्धति पर आधारित चार मेट्रो शहरों के कृषि केन्द्र मुख्य हब के रूप में काम करेंगे जबकि द्वितीयक शहरों में स्थापित हब स्पोक के रूप में काम करेंगे। द्वितीयक शहरों में लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि शामिल हैं। यह सोच रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के दिमाग की उपज है जिन्होंने हाल ही में 7000 रेलवे स्टेशनों के नजदीक कृषि खुदरा केन्द्रों की स्थापना का आह्वान किया था।

मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार रेलवे ने बेकार पड़े गोदामों और रेलवे की बेकार पड़ी भूमि को इन कंपनियों को खुदरा कारोबार के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया है और इसके लिए कंपनियां आवश्यक बुनियादी ढांचों का निर्माण करेगी। बड़े पार्किंग सुविधाओं के अलावा इन हबों पर माल की देखरेख, रेफ्रिजेरेशन, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं के साथ-साथ शार्टिंग और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध होगा। ये हब कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित इनलैंड कंटेनर डिपो से बड़े होंगे। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने यह भी वादा कंपनियों के साथ किया है कि उन्हें इन हबों तक आने-जाने के लिए मूल्यवर्द्धित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। मंत्रालय शीघ्र ही स्थानों की सूची और मूल नीति के साथ इन कंपनियों के साथ विचार-विमर्श करेगी। एक बार प्रारम्भिक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिये जाने के बाद अंतिम रूप रेखा दो-तीन महीनों के भीतर प्रकाश में आ जायेगी।

प्राकृतिक आपदा जशपुर के टमाटर किसानों के लिए बनी वरदान

पत्थलगांव ❒ वार्ता।

कभी कम बारिश और कभी ओलावृष्टि को आमतौर पर किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा ही कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पिछले दिनों टमाटर की बुवाई के दौरान आयी यह प्राकृतिक आपदा किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण यहां टमाटर उत्पादन में 50 से 60 प्रतिशत तक की गिरावट आयी है। जिस कारण इन दिनों किसानों को टमाटर के तीन गुना अधिक दाम मिल रहे हैं। आमतौर पर टमाटर उत्पादन के लिहाज से दिसम्बर-जनवरी माह में आने वाली फसल को यहां ज्यादा भाव नहीं मिलते। इस दौरान टमाटर उत्पादक अपनी फसल को महज 40 से 50 रुपये प्रति कांवर के भाव बेच जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इस मौसम में टमाटर की कीमत घटकर 20 से 25 रुपये प्रति कांवर हो जाती है और किसान टमाटर बाजार तक लाने के बजाय खेतों में ही मवेशियों को खिला देते हैं। जशपुर जिला किसान संघ के अध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्र के मुताबिक आपदा के कारण टमाटर की फसल खराब हो गयी थी जिससे किसान पहले तो मायूस हो गये थे। लेकिन बाद में उम्मीद से ज्यादा भाव मिलने पर इनकी कीमत बढ़कर 200 रुपये प्रति कांवर तक पहुंच गयी। उड़ीसा और झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों से

भी टमाटर की आवक कम होने के बाद पत्थलगांव के टमाटरों की मांग बढ़ गयी है।

लुडेग के प्रमुख टमाटर उत्पादक खितिश खुंटिया के मुताबिक टमाटर में फूल लगने के बाद यहां ओले पड़ने से टमाटर की 50-60 प्रतिशत फसल खराब हो गयी थी लेकिन जनवरी के आफ सीजन में मांग बढ़ जाने से इसकी कमी हो गयी और दाम बढ़ गये। आलम यह है कि अब यहां किसान इस आपदा को वरदान मानने लगे हैं।

मांग बढ़ जाने से पड़ोसी प्रांतों के व्यापारी टमाटर की खरीद के लिए यहां के साप्ताहिक बाजारों में आने लगे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा टमाटर उपजाने वाले जशपुर जिले में किसानों को कभी सरकारों से कोई सुविधा नहीं मिली है। उल्टे उन्हें सरकार की बेरुखी ही मिली है और टमाटर किसानों को शिकायत है कि उन्हें लाभान्वित करने वाली योजनाऐ फाइलों में सिमटकर रह गयी है।

आईबीएम ने भारत-दक्षिण एशिया को बनाया नया क्षेत्र

नई दिल्ली ❒ वार्ता।

कम्प्यूटर तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी आईबीएम ने एशिया प्रशांत में भारत-दक्षिण एशिया को नये क्षेत्र के तौर पर चिहिन्त किया है जो उसके व्यापारिक क्षेत्र आसियान से अलग हो गया है।

कंपनी के मुताबिक इस नये क्षेत्र में भारत के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता शंकर अन्नास्वामी करेंगे, जो जून 2004 से आईबीएम इंडिया के महाप्रबंधक है।

आईबीएम इंडिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ग्रेटर चायना ग्रुप, जापान और कोरिया भी अलग-अलग क्षेत्र हैं। कंपनी अगले तीन वर्ष में भारत में छह अरब डॉलर के निवेश की घोषणा कर चुकी है।

आईटीसी बेहतर व्यावसायिक गतिविधियों को अपनाने में विक्रेताओं की मदद करेगा

बंगलुरू, ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

अपने व्यवसायों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के उद्देश्य से आईटीसी ने अपने विक्रेताओं को सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक गतिविधियों को अपनाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया है। अपने स्सटेनबलिटी रिपोर्ट 2006 में कम्पनी ने कहा है कि अब तक वह अपने एफएमसीजी कारोबार के क्षेत्र में 120 ऐसे विक्रेताओं का सहयोग कर चुकी है। अगरबत्ती के कारोबार में कंपनी ने 8 विक्रेताओं के माध्यम से उत्पादन तैयार किया है, ये सभी गृहउद्योग क्षेत्र में हैं और खासतौर पर इसमें काम करने वाली महिलाएं हैं। इनमें से 6 विक्रेताओं को आईएसओ-9001 प्रमाणपत्र हासिल हुआ है।

कंपनी ने वृहत पैमाने पर जल संरक्षण की दिशा में भी काम शुरू किया है। इसकी जल संभरण विकास परियोजना के एक हिस्से के रूप में 16 जिलों के 325 गांवों में 15506 किसानों को लाभ मिल रहा है। लगभग 1011 जल संभरण ढांचा का निर्माण किया गया है और इन ढांचों के माध्यम से लगभग 10277 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त 18.99 मिलियन किलोलीटर पानी के भंडारण की क्षमता मौजूद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन पहलों के माध्यम से आईटीसी लगातार चौथे साल ''जल सकारात्मक'' कंपनी बनी है। वर्ष 2005-06 में कुल 4.62 मिलियन किलोलीटर ताजे पानी के उपयोग की तुलना में कंपनी ने अपनी जल संभरण गतिविधियों के माध्यम से 19.60 मिलियन किलोलीटर पानी के भंडारण की क्षमता का निर्माण कर लिया है। यह उपलब्धि इनकी इकाईयों के साथ-साथ नमी की कमी वाले देश के अन्य जिलों में स्थापित की गई है।

अगले पांच वर्षों में कंपनी की 50 हजार हेक्टेयर भूमि को मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की योजना है। इसके लिए अतिरिक्त 1500 जल संभरण ढांचों का निर्माण किया जाएगा ताकि और 28 मिलियन किलोलीटर पानी के भंडारण की क्षमता विकसित की जा सके।

ठोस कचरा प्रबंधन पहल के तहत कंपनी ने तीन योजनाएं तैयार की हैं, जिसके तहत कंपनी के अंदर ठोस कचरे की मात्रा में कमी लाई जायेगी और अगले 2 वर्षों में कंपनी को शून्य ठोस कचरा वाली कंपनी के रूप में पहचान दिलाई जायेगी।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रति इकाई उत्पादन से कचरे की कमी पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा ताकि कचरे की उत्पत्ति में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनी द्वारा संचालित गतिविधियों से उत्पन्न सभी कचरों का पुनर्चक्रण किया जा सके और कच्चे माल से कम से कम कचरा पैदा हो सके। पहली दो पहल के तहत वर्ष 2005-06 में 78.7 प्रतिशत उत्पन्न सभी प्रकार के कचरों का पुनर्चक्रण किया गया। कंपनी को उम्मीद है कि अगले दो वर्षों में 100 प्रतिशत पुनर्चक्रण के माध्यम से शून्य ठोस कचरा उत्पन्न करने वाली कंपनी बन जाएगी।

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से निपटने के लिए कंपनी ने अपने प्रयासों के तहत कुछ विशेष प्रकार के ऊर्जा के खपत को कम करने का निर्णय लिया है, जिससे की ग्रीन हाउस गैसों के निर्माण में कमी लाई जा सके। इसके लिए वृहत्त पैमाने पर वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के सुधार में कंपनी अपना योगदान देगी। इन प्रयासों से 41000 हेक्टेयर भूमि को हरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।

मौसम की भविष्यवाणी के संबंध में महाराष्ट्र के किसानों को एसएमएस की सुविधा

पुणे, ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

दो महीने पहले सांगली में बेमौसमी वर्षा के बावजूद 55 वर्षीय किसान सुभाष दत्तात्रेय उन 200 मुख्य रूप से अंगूर उत्पादक सौभाग्यशाली किसानों में शामिल थे जो अपनी 40 एकड़ अंगूर की खेती को बचाने में सफल हुए। वर्षा से एक दिन पहले उन्हें एक एसएमएस प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें वर्षा के संबंध में चेतावनी दी गई।

दत्तात्रेय को प्रति महीने एसएमएस हासिल करने के लिए 50 रुपये खर्च करने पड़ते हैं लेकिन इस एसएमएस के करिश्मे के चलते वो लगभग 1 लाख रुपये के नुकसान से बचने में सफल रहे। दत्तात्रेय सहित सभी किसानों को सप्ताह में मौसम से संबंधित औसतन 2-3 संदेश प्राप्त होते हैं जिसमें अगले कुछ दिनों के बारे में बादल और वर्षा के संबंध में भविष्यवाणी उपलब्ध कराई जाती है।

पिम्पल गांव के एक किसान अरूण मोरे का कहना है कि इससे पहले हमें इनसेट चित्रों के जरिये इंटरनेट के माध्यम से मौसम संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती थीं, जिसका अनुमान केवल 40-45 प्रतिशत तक सही होता था लेकिन पिछले लगभग डेढ़ महीने से आईआईटी बॉम्बे के डेवलपमेंटल इंफॉरमेटिक्स लैबोरेट्री द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र बारामती से हासिल मौसम संबंधी सूचनाओं को एसएमएस द्वारा किसानों को पहुंचाने की प्रक्रिया से हालात बिल्कुल बदल गये हैं। उन्होंने बताया कि इन संदेशों की सही होने की संभावना 99 प्रतिशत तक है। उन्होंने कहा कि एसएमएस संदेशों के बारे में हमारी सोच बिल्कुल बदल गई है। इसके माध्यम से इस क्षेत्र के किसान इतने सक्षम हो गये हैं कि फंफूदनाशकों पर होने वाले 1000-2000 रुपये प्रति एकड़ के खर्च को बचाया जा सके।

एग्रोकोम नाम की बोम्बे स्थित आईआईटी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के एक समूह ने राज्य में इस संदेश क्रांति का शुभआरंभ किया और प्रौद्योगिकियों का फायदा कृषक समुदाय तक पहुंचाने का निर्णय लिया। एग्रो कॉम का एक पोर्टल ''आल मोस्ट ऑल क्योशच्नस एनसर्ड'' नाम से है जिसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। इसके माध्यम से किसानों के सभी प्रकार के सवालों का जवाब उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ किसानों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी चला जा रहा है जहां किसानों के लिए वेब तथा मोबाइल कृषि सेवा उपलब्ध है।

एग्रो कॉम के प्रबंध निदेशक अनिल बाहुमणि ने बताया कि हमने इस सेवा की शुरुआत बारामती में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र की सहभागिता में इस क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर की थी।

विपणन प्रमुख शांतनु ईनामदार ने बताया कि यह भी प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को संदेशों के माध्यम से आर्द्रता और तापमान के संबंध में भी सूचनाएं दी जा सके।

40 वर्षीय किसान राजेन्द्र कोद्सकार ने बताया कि अंगूर की खेती आर्द्रता की स्थिति और मौसम की परिस्थितियों को लेकर काफी संवेदनशील है। यही कारण है कि एग्रो काम के अधिकांश ग्राहकों में अंगूर उत्पादक ही शामिल हैं।

कॉफी वर्षा बीमा योजना को मंत्री समूह की मंजूरी

बंगलोर, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

मंत्रियों के समूह ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पारंपरिक कॉफी उत्पादन में लगे 146579 किसानों के लिये वर्षा बीमा योजना को मंजूरी दे दी है लेकिन मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही यह योजना लागू हो सकेगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल इस योजना को जनवरी के आखिर तक मंजूरी दे सकता है। यदि यह योजना आगामी फसल से लागू की जानी है तो मंत्रिमंडल को इसे जनवरी के आखिर तक पास करना होगा। नवंबर-दिसंबर में अरेबिका बींस शुरू हो जाती है और रोबुस्ता की कटाई उसके कुछ महीने बाद शुरू हो जाती है। इस योजना के अनुसार मौजूदा फसल में पारंपरिक इलाकों में मानसून के दौरान अगर 62 दिन वर्षा होती है तो किसानों को फायदा होगा।

भारत के कॉफी उत्पादकों को उम्मीद है कि इस योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने से उन्हें बहुत फायदा होगा। इस योजना को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लागू करेगी और कॉफी बोर्ड के पास पारंपरिक इलाकों में इस योजना को बेचने के लिये केवल फरवरी का समय होगा। कॉफी में मार्च से फूल आना शुरू हो जाते हैं।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने पिछले 12 महीनों में कॉफी बोर्ड और कॉफी उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह योजना विकसित की है। योजन बनाते समय यह ध्यान रखा गया कि वर्षा पर किसानों का कोई नियंत्रण नहीं है इसलिये फसल को वर्षा से सुरक्षा मिलनी चाहिए। कम वर्षा के कारण फसल पर फूल आने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और अधिक वर्षा से फूल झड़ जाते हैं इसलिये किसानों को कम वर्षा के साथ-साथ अधिक वर्षा से भी नुकसान होता है। किसान या तो फूल खिलने अथवा मानसून की वर्षा से बचाव के लिये सुरक्षा कवर ले सकेंगे। इस योजना का कुल बीमा धन अरेबिका के लिये 30 हजार प्रति हेक्टेयर तक तथा रोबुस्ता के लिये 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है।

भारत के 98 प्रतिशत से अधिक कॉफी उत्पादक छोटे किसान हैं इसलिये इस योजना को सब्सिडी दी जायेगी। छोटे किसानों को एक हजार और दो हजार रुपये के बीच प्रीमियम पर एक हजार रुपये की सब्सिडी दी जायेगी लेकिन दो हजार रुपये से अधिक प्रीमियम पर पचास प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी। पारंपरिक इलाकों को वर्षा के ऐतिहासिक नमूने के आधार पर 43 क्षेत्रों में विभाजित किया गया और उसी के अनुसार प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

कॉफी बोर्ड के उत्पादक सदस्य अनिल भंडारी के अनुसार यह योजना अगली फसल से लागू होनी है क्योंकि इस योजना के लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी से भारत के 178308 कॉफी उत्पादकों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा

क्योंकि वे 1999 से 2004 के दौरान पांच वर्षों की बुरी अवधि से अभी तक नहीं निकल पाये हैं। इस अवधि के दौरान दुनिया में अधिक शेष भंडार के कारण औसत कॉफी उत्पादन कम हुआ था और उसके फलस्वरूप कॉफी उत्पादकों की आमदनी घट गयी थी।

भारत कपास व्यापार में अमरीका का प्रतिद्वंद्वी

मुम्बई, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

भारत चीन को कपास निर्यात करने के व्यापार में अमरीका का प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरा है। अमरीका के कपास उत्पादक चीन को फाइबर का निर्यात करते हैं। गौरतलब है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार भारत की नजर चीन के बड़े व्यापार पर है। अमरीकी कपास उद्योग के लिए विपणन के रूप में कार्य कर रही अंतर्राष्ट्रीय कपास परिषद के अध्यक्ष डेविड बर्न्स के अनुसार भारत की नजर अमरीका की तरह चीन जैसे प्रमुख देशों पर है। श्री डेविड बर्न्स बेल्टवाइट कॉटन इंडस्ट्रीज की वार्षिक बैठक के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय कपास परिषद के कार्यकारी निर्देशक एलन तेरहर के अनुसार भारत के कपास निर्यातक चीन में अपना निर्यात बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

अमरीकी कृषि विभाग की मांग आपूर्ति संबंधी मासिक रिपोर्ट में चीन में 2006-07 के दौरान 17.25 मिलियन गांठों के आयात का पूर्वानुमान लगाया गया है। भारत से 4.1 मिलियन गांठों का निर्यात होने का अनुमान है। अमरीका कपास का सबसे बड़ा निर्यातक है। 2006-07 के दौरान अमरीका से 16 मिलियन गांठों के निर्यात का अनुमान है। इसमें से ज्यादातर चीन और तुर्की में निर्यात होना है। अमरीकी फाइबर के लिये तुर्की दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।

तेरहर के अनुसार भारत में कम माल भाड़े के कारण वहां की कपास चीन के उपभोक्ताओं के लिये सस्ती पड़ती है। इन दोनों अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि दो एशियाई महाशक्तियों में मांग का दोहन पूरी तरह नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये दोनों कपास को वस्त्रों में परिवर्तित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं और इसका मुख्यत: अमरीका को निर्यात किया जाता है। अमरीकी कृषि विभाग के अनुसार 2006-07 में चीन में 50 मिलियन गांठों की खपत का अनुमान है जबकि भारत में 17.8 मिलियन गांठों का है। तेरहर के अनुसार भारत और चीन में आमदनी बढ़ने के कारण आगामी वर्षों में कपास के बाजार में बहुत विस्तार होगा इसलिये इन दोनों देशों में मांग की व्यापक संभावना है। चीन में अनाज उत्पादन की ओर रुझान बढ़ने और इसकी आवश्यकता के कारण कपास उत्पादन बाधित होने की आशंका है। भारत में पर्याप्त भूमि तो है परंतु उसे मांग पर ध्यान रखना होगा।

अरेबिका कॉफी का निर्यात बढ़ने की उम्मीद

बंगलोर, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

भारत में पैदा होने वाली अरेबिका कॉफी बींस को मौजूदा कैलेंडर वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छे भाव मिलेंगे। ये सब ब्राजील में उत्पादन घटने के कारण होगा। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। वहां मुख्य रूप से अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है। इस सीजन में वहां 31.1 मिलियन बोरी से लेकर 32.3 मिलियन बोरी कॉफी उत्पादन की उम्मीद है। इस प्रकार पिछले सीजन के 42.5 मिलियन बोरी की तुलना में यह बहुत कम है। ब्राजील से कॉफी का निर्यात भी कम होने की आशंका है। इस वर्ष 2006 के 24.4 मिलियन बोरी की तुलना में केवल 21.7 मिलियन बोरी का निर्यात होने की उम्मीद है जिसके कारण 2007 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अरेबिका की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर पैदा होने का अनुमान है।

भारतीय कॉफी निर्यातक संघ के अध्यक्ष रमेश राजा के अनुसार ब्राजील में उत्पादन घटने के अनुमान से आगामी दिनों में भारतीय अरेबिका के भाव बढ़ेंगे। भारत में नवंबर से अरेबिका की कटाई शुरू हो गयी है जबकि ब्राजील में कटाई जून में शुरू होगी और सितंबर तक जारी रहेगी। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अरेबिका के भाव 120 सेंट प्रति पाउण्ड बोले जा रहे हैं। ब्राजील में उपज घटने के अनुमान के कारण अरेबिका के भाव 132 सेंट प्रति पाउण्ड तक जाने की उम्मीद है। इस प्रकार आगामी महीनों के दौरान इसमें वर्ष दर वर्ष के आधार पर 10 से 12 प्रतिशत उछाल आने की संभावना है। इस परिदृश्य का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा। जहां अरेबिका के भाव मौजूदा 94 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो जायेंगे।

कृषि में चार फीसदी वृद्धि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी जरूरी : पवार

नई दिल्ली, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

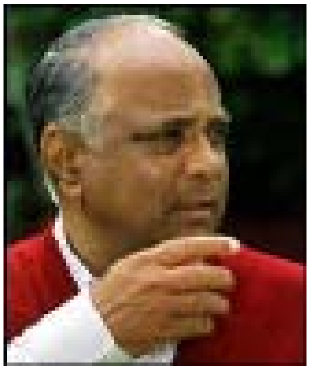

कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को अपनाने का जोरदार समर्थन किया है। प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने आये प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए श्री पवार ने कहा कि विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, जल संरक्षण, बीज, ई-कृषि और विस्तार में क्षेत्र में इस प्रकार की भागीदारी की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

श्री शरद पवार कहा कि राज्यों और प्रवासी भारतीयों को इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदारों की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में बड़े बदलाव आयेंगे और बड़े निवेश होंगे। श्री पवार ने कहा कि प्रवासी भारतीय और निजी क्षेत्र गुणवत्ता वाले बीजों और लघु सिंचाई प्रणाली के उन्नयन में बेहद सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं। देशभर में ठेका खेती और ऑन लाइन कृषि क्षेत्र में निजी सार्वजनिक भागीदारी की बेहद संभावनाएं हैं। कृषि ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को तुलनात्मक रूप से लाभ प्राप्त है और पर्वतीय तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों, जहां कृषि रसायनों का कम या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, को जैव कृषि के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे ही जैव ईंधन के अनुमानित महत्व और पेट्रोल और डीजल इंजनों में इसके इस्तेमाल को शुरू करने के लिए एक रूपरेख तैयार करने की भी जरूरत है।

अनुसंधान और विस्तार के क्षेत्र में भी सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए संयुक्त रूप से अभिनव मॉडलों को विकसित करने में प्रवासी भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री पवार ने कहा कि विभिन्न देशों में रह रहे विभिन्न प्रांतों के दो करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीयों की पेशेवर विशेषज्ञता, व्यापारिक बुद्धि और निवेश क्षमता का भारत के विकास की कार्यनीतियों में इस्तेमाल की जरूरत है।

रतनजोत की खेती के लिए जमीन देने का विरोध

जयपुर, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

राजस्थान सरकार रतनजोत व करंज के उत्पादन व प्रसंस्करण के लिए प्रदेश में करीब 57 लाख हेक्टेयर गैर कृषि योग्य बंजर भूमि कुछ समूहों और निजी कम्पनियों को मुफ्त व रियायती दर पर आवंटित करेगी। प्रदेश में बायो डीजल क्रांति की बड़ी फसल करते हुए राज्य मंत्रिमण्डल ने यह फैसला किया। मुख्य सचिव या कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समितियां कम्पनियों व चुनिन्दा समूहों को जमीन आवंटन करेंगी।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. बुलाकीदास कल्ला ने करीब छह माह बाद मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा कंपनियों को रतनजोत की खेती के

नाम पर साढ़े चौदह लाख हेक्टेयर भूमि देने के निर्णय की निंदा करते हुए इसे किसान की पीठ में छुरा घोंपने के समान बताया है। यहां जारी बयान में डॉ. कल्ला ने कहा कि जमीन पर सबसे पहला हक किसान का है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आरंभ से जमीन घोटालों में लिप्त रही है। अब 48.49 लाख हेक्टेयर जमीन कम्पनियों, सहकारी समितियों, भाजपा समर्थित एनजीओ को देने से और भी बड़ा घोटाला होने की आशंका है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि यह जमीन भूमिहीन किसानों को मिलनी चाहिए। राजस्थान के किसान को कम पानी में खेती करने तथा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का अनुभव है। इसका उदाहरण इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में किसानों द्वारा लाई गई हरित क्रांति है। डॉ. कल्ला ने कहा कि किसान व जमीन का पवित्र रिश्ता है जिसे कांग्रेस कभी टूटने नहीं देगी। सहकारी समितियों के पंजीयन शुल्क को तीन गुणा बढ़ाये जाने की निंदा करते हुए उन्होंने बताया कि इसमें किसानों पर अतिरिक्त कर भार बढ़ेगा। सरकार बड़े पूंजीपतियों को राहत दे रही हैं किंतु किसानों का पंजीयन शुल्क बढ़ा रही हैं। इसी कारण भाजपा सरकार को गांव, गरीब एवं किसान विरोधी सरकार की संज्ञा दी जा रही है।

मसूर मजबूत, अन्य दलहनों में नरमी की संभावना

नई दिल्ली ❐ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

उड़द : उड़ीसा में कटाई जारी रहने और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी कटाई होने के साथ-साथ 8 जनवरी से शुरू हुए सप्ताह के दौरान उड़द बाजारों में धारणा स्थिर बनी रही। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में लगभग 3 लाख टन उड़द होने की संभावना है। इस सप्ताह नाफेड ने 35168 टन बिकवाली की जिससे बाजार में नरमी को बल मिला। म्यामां में उड़द के एफएक्यू भाव 660 डॉलर प्रति टन बोले जा रहे हैं जिसके कारण आयात परिदृश्य धुंधला है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि एमएमटीसी 5 हजार टन उड़द आयात करने का विचार छोड़ देगी। नाफेड ने भी आयात के संबंध में कोई फैसला नहीं किया है। अगले सप्ताह उड़ीसा से आवकें शुरू होने के बाद कीमतों में नरमी की संभावना है लेकिन तब तक सीमित दायरे में घटबढ़ की संभावना है।

चना : चना बाजारों में मिली-जुली धारणा बनी रही। जिन बाजारों में नई आवकें शुरू हो गयी है वहां कीमतों में और नरमी देखी गयी लेकिन अन्य बाजारों में घटते स्टॉक के कारण कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कटाई गति पकड़ चुकी है जबकि म.प्र. में फरवरी के प्रारंभ में छिटपुट कटाई शुरू होने की संभावना है। इस बार 5.5 मिलियन टन उत्पादन की संभावना है जबकि खपत 5 मिलियन टन रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में कीमतों में नरमी की संभावना दिखाई देती है। शायद इसीलिए नाफेड दलहन आयात करने के फैसले में देरी कर रहा है।

तूर : नई फसल की अच्छी आपूर्ति के कारण तूर के भाव स्थिर से लेकर मामूली कमजोर बने रहे। स्टॉकिस्ट ऊंची कीमतों पर लिवाली के इच्छुक नहीं है लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में कम उत्पादन के मद्देनजर अधिक गिरावट की आशंका नहीं है। बर्मी तूर के एफएक्यू भाव 560 डॉलर प्रति टन रहने के कारण आयात कम हो रहा है। एमएमटीसी अब केवल एक हजार टन तूर आयात करेगी जबकि इससे पहले पांच हजार टन आयात की योजना बनाई गई थी।

मसूर : मसूर स्टॉक कम होने के कारण इस सप्ताह मसूर बाजारों में मामूली मजबूती देखी गयी। म.प्र. में अच्छी फसल खड़ी है जहां मार्च में कटाई शुरू होने की संभावना है। उ.प्र. के कुछ इलाकों में सर्दियों में वर्षा के अभाव और भूमि में नमी की स्थिति के कारण मसूर समय से पहले पकने की संभावना है जिससे इसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। ऑफ सीजन में भाव मामूली रूप से मजबूत रहने की संभावना है लेकिन अन्य दलहनों की कटाई के कारण तेजी की संभावना सीमित है।

मटर : ऑफ सीजन में देशी मटर की कम आपूर्ति और निर्यातकों के मामूली ऊंचे भावों के चलते मटर की कीमतों में मामूली मजबूती देखी गयी। नई फसल मार्च में ही आने की संभावना है और तब तक घटते स्टॉक से देशी मटर की कीमतों पर दबाव बना रहेगा। कनाडा मूल के सफेद मटर के भाव में वृद्धि से और बल मिला। चेन्नई में केनेडियाई मटर के भाव 300-310 डॉलर प्रति टन बोले गये। कटाई शुरू होने तक तेजी का रुख जारी रहने की संभावना है परंतु चने की कीमतों में गिरावट के कारण यह तेजी सीमित रहेगी।

विदर्भ में किसानों की आत्महत्या जारी

नागपुर, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

विदर्भ के किसानों के लिए कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। नए साल के पहले हफ्ते में 13 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पिछले वर्ष 1050 किसानों ने आत्महत्या की और सबसे अधिक इसी क्षेत्र के किसानों ने ही की। यह सब कृषि क्षेत्र के संकट का बखान करता है। गत रविवार तक जिन 13 किसानों ने आत्महत्या की उनकी पहचान हो चुकी है।

विदर्भ जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष किशोर तिवारी के अनुसार अत्यधिक प्रभावित यवतमाल, वर्धा, अकोला, अमरावती, वाशिम और बल्धाणा जिलों में हजारों कपास उत्पादक अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ हैं क्योंकि राजकीय कपास खरीद योजना के तहत खरीद करने वाले सहकारी कपास विपणन संघ के 86 खरीद केन्द्र बंद हो गये हैं। तिवारी का दावा है कि संघ के अधिकारियों ने वानी, घटंणी और परवा सहित कम से कम 22 केन्द्र यह कहते हुए बंद कर दिये कि वे भंडारण स्थल को खाली कर चुके हैं। संघ के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि कुछ खरीद केन्द्र बंद हो गये हैं और कहा कि ये केन्द्र 11 जनवरी से खुल रहे हैं। सरकार 5 दिसंबर को वानी में पुलिस की गोलीबारी के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1990 रुपये प्रति क्विंटल पर कपास की खरीद में सक्रिय हुई और ऐसा कुछ दिनों तक जारी रहा। लेकिन फिर किसानों को राम-भरोसे छोड़ दिया गया। संघ के खरीद केन्द्र अचानक बंद होने का फायदा उठाते हुए निजी व्यापारियों ने भाव घटा दिये और किसानों को 1800 रुपये से कम भुगतान कर रहे हैं। किशोर तिवारी मकर संक्रांति के अवकाश के बाद खरीद केन्द्र फिर खोलने की घोषणा पर दृढ़ थे।

अवेस्थाजीन को मिला चावल जीन का पेटेंट

मुम्बई, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

अवेस्थाजीन ने घोषणा की है कि उसने भारतीय पेटेंट कार्यालय से एजीटीएसएएल 11 चावल जीन की क्लोनिंग और सीक्वेंसिंग पर पेटेंट हासिल किया है। यह किस्म आईआर-64 में खारेपन के प्रति सहनशीलता का गुण विकसित करके तैयार की गयी है। इस खोज से भारत में चावल में नमक के प्रति सहनशीलता विकसित करने में सफलता मिलने की उम्मीद है। नमक के प्रति सहनशीलता कार्यक्रम कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि खेती करने के मौजूदा तरीकों और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल से अत्यधिक लवणता बढ़ी है जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि बड़े पैमाने पर खेती के लिए अनुपयुक्त होती जा रही है। यह तकनीक इस मायने में और लाभदायक होगी कि इसे थोड़े से समय में ही किसी अन्य फसल में भी हस्तांतरित किया जा सकेगा क्योंकि यह तकनीक किसी फसल विशेष के लिए नहीं है। अवेस्था जीन ग्रेन टेक्नोलोजी प्रा.लि. के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. विल्लू मोरावला पटेल के अनुसार इस पेटेंट तकनीक से अवेस्थाजीन को किसानों के हित के लिए नवीन समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। अवेस्थाजीन को आनुवांशिक रूप से संशोधित बाजरे के लिए दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पेटेंट मिलने वाला है। अवेस्थाजीन ने एग्रोबेक्ट्रीयम और बायोलिस्टिक ट्रांसफोर्मेशन के माध्यम से बाजरे की संशोधित किस्म तैयार की है।

नई पुनर्वास नीति शीघ्र – प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि एक नई पुनर्वास नीति को अगले तीन महीनों में अंतिम रूप दे दिया जायेगा। यह नीति ज्यादा प्रगामी, मानवीय और हमारी अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों के दीर्घकालिक कल्याण की दृष्टि से अनुकूल होगी। उन्होंने कहा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र

और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए ऐसी नीति बनायी जायेगी जिससे अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के मालिकों के पुनर्वास का सर्वमान्य समाधान हो सके।

यहां फिक्की के वार्षिक आम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हमारे देश में औद्योगिकीकरण का विस्तार एक विवादित मुद्दा बने। उन्होंने कहा कि जमीन का अधिग्रहण, लोगों का विस्थापन और उनका पुनर्वास तथा उन्हें फिर से बसाने जैसे मुद्दे कारगर तथा पारददर्शी तरीके से निपटाये जाने चाहिए। ये मुद्दे निपटाए जा सकते हैं और निपटाए भी जायेंगे। फिक्की के 79वें वार्षिक आम सम्मेलन का विषय था- 'भारत उदय: वृद्धि, शासन और समान अवसर की चुनौती।'

प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे वित्त मंत्री तथा निवेश आयोग से एक ऐसी संस्थागत प्रणाली का सुझाव देने के लिए कहेंगे जिससे बड़े स्तर की परियोजनाएं चाहे वे निजी क्षेत्र की हों या सार्वजनिक क्षेत्र की, दोनों को सुविधा मिले ताकि वे शुरू में बनाई गई योजना के अनुसार शुरू हो सकें।

सामाजिक रूप से दायित्वपूर्ण कारोबार का आह्वान करते हुए डॉ. सिंह ने भारतीय उद्योग से कहा कि वे समाज के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने की जरूरत के प्रति संवेदनशील बनें ताकि ये वर्ग भी आर्थिक तथा सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं से समान रूप से फायदा उठा सके। डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा कि औद्योगिक विकास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई फायदा न मिले। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। औद्योगिक विकास ऐसा होना चाहिए कि इससे समाज के सभी वर्गों को फायदा मिले और हम सभी ऐसा करने के लिए प्रयास करेंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी कर व्यवस्था उदार, लेकिन समान होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अब साझा आम बिक्रीकर की दिशा में आगे बढ़ेंगे और वैट की दरों में भी बेहतर तालमेल कायम करेंगे। आगे चलकर हमारी कर व्यवस्था में बहुत ज्यादा रियायतें नहीं होनी चाहिए। इससे कर प्रशासन में अनावश्यक जटिलताएं आ जाती हैं और इनके दुरूपयोग की आशंका बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे हम भारत को वैश्विक वित्त प्रणाली के साथ जोड़ते जायेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था की योग्यता में हमारा विश्वास बढ़ता जायेग, हम ऐसी विदेशी मुद्रा व्यवस्था में धीरे-धीरे प्रवेश कर जायेंगे, जिसमें प्रतिबंध कम होंगे। डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा कि तेजी से होते विकास और प्रखर बाजार की चर्चाओं में हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमें निवेश की उच्च दर को बनाये रखना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है, रोजगार के और ज्यादा अवसर पैदा करना है, हमारी कृषि व्यवस्था में नई तेजी लानी है और गरीबी, अज्ञानता तथा बीमारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी रखनी है। बिजली क्षेत्र में सुधारों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फरवरी में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है।

गोल्डन लीफ अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन कोच्चि में

नई दिल्ली, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

गोल्डन लीफ अवार्ड के लिए तीसरी दक्षिण भारतीय चाय प्रतियोगिता मार्च 2007 में कोच्चि में आयोजित की जायेगी। यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया (उपासी) इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। आयोजन समिति के संयोजक एन. धर्मराज के अनुसार प्रत्येक कृषि जोन से चाय के लिए लोगों में विशेष परतंत्र विद्यमान है और उसकी खास विशेषता है। कुछ क्षेत्रों को भौगोलिक संकेतक सूची में पहली बार शामिल किया गया। इसकी अंतिम जांच कोच्चि में होगी। इससे पहली की प्रतियोगिता की तरह इसमें अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी होगी जिसमें प्रमुख आयातक देश और प्रमुख लिवाल भी शामिल होंगे। इससे पहले यह प्रतियोगिता 2005 में कून्नूर में हुई थी उसके बाद दुबई में आयोजित की गयी। इस प्रतियोगिता को लोगों का अच्छा समर्थन मिला। बेहतरीन गुणवत्ता की चाय के उत्पादन और दक्षिण भारतीय चाय के बारे में जागरूकता फैलाने में चाय बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे दक्षिण भारत से चाय का निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है। ब्लैक आर्थोडॉक्स और सीटीसी चाय में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। अन्नामलाई, ऊंची श्रेणियों, नीलगिरी, त्रावणकोर और कर्नाटक, नेल्लियमपेथी, मदुरई, सिंगमपट्टी, क्विलॉन, तिरुअनंतपुरम और कन्याकुमारी जैसे क्षेत्रों से सीटीसी के

जैविक रूपों से भी कड़ी प्रतिस्पर्द्धी होगी। प्रतियोगिता के लिए पहले स्तर की छटनी 10 मार्च तक पूरी होगी। कीटनाशकों के अपशिष्ट के लिए तकनीकी विश्लेषण 16 मार्च तक होगा। चाय के परीक्षण का अंतिम सत्र 21 मार्च को होगा।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन

नई दिल्ली, ❒ ऐग्रीवाच न्यूज सर्विस।

केन्द्रीय लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्री श्री महावीर प्रसाद ने 6 जनवरी, 2007 को उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, कपड़ा उद्योग पर प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, हस्तकला आदि इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण रहे। प्रदर्शनी 10 जनवरी, 2007 तक खुली। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री महावीर प्रसाद ने कहा कि सरकार उद्यमियों और युवाओं को उनके अपने उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से इस क्षेत्र का औद्योगिक पिछड़ापन दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के लिए नई योजनाएं लागू करने का आग्रह किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री एच. पी. कुमार भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निगम ने निर्यात ऋण बीमा के लिए कई बैंकों के साथ हाथ मिलाया है।